556वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 02 मार्च 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 556वीं बैठक दिनांक 02/03/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. <u>प्रकरण क्रमांक 9028/2022 – मेसर्स मैग्नीज ओर (इंडिया) लि., गॉव एवं तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट (म.प्र.) मैग्नीज ओर माइन, खसरा नं. 154/1, 155/2, 156/2, 157/2, 174/2, रकबा 04.42 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर–1200 टीपीए, गॉव एवं तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 154/1, 155/2/156/2, 157/2, 174/2, रकबा 04.42 हेक्टेयर, गॉव एवं तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वताया गया कि प्रकरण मुख्य अयस्क का है जिसका कुल रकबा 4.42 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज के अनुसार मैगनीज माइन में पेड दिखाई दे रहे है, एक पक्का रोड़ 100 मीटर पश्चिम दिशा में स्थित है एवं रहवासी बस्ती 115 मीटर पश्चिम दिशा में एवं 345 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, एवं एक जल संग्रहण क्षेत्र भी दक्षिण पूर्व दिशा में 127 मीटर पर स्थित हैं । प्रस्तावित खदान ओपन कास्ट से माइनिंग की जाना प्रस्तावित है अतएवं पी.पी. द्वारा किसी भी प्रकार की भूमिगत खनन (Under Ground Mining) कार्य नही किया जावेगा । अतएवं उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

जारी मानक टी.ओ.आर परिशिष्ठ ''डी'' में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ. आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित माइन प्लान के अनुसार लीज एरिया के अंदर एक जल नहर स्थित है, जो स्थानातंरित हेतु प्रस्तावित है परियोजना प्रस्तावक उक्त नहर का स्थानांतरण संबंधित विभाग से आवश्यक अनुमति लेने के पश्चात् ही उक्त विभाग से समन्वय से ही करवायेगा जिससे किसी प्रकार का नहर के जल वितरण में नुकसान नही हो पाये तथा की गई कार्यवाही की प्रगति ई.आई.ए रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगे ।
2. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊॅचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
3. लीज एरिया के पूर्व दिशा में 127 मीटर पर एक बड़ा जल निकाय तथा रोड़ स्थित है अतएव पी.पी. द्वारा इनके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. चूॅकि प्रस्तावित क्षेत्र रहवासी क्षेत्र, नहर व जल संरक्षण क्षेत्र है, अतः ग्राउण्ड बाइब्रेशन स्टडी कर रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।

2. <u>प्रकरण क्रमांक 9029/2022 – मेसर्स मैग्नीज ओर (इंडिया) लि., गॉव एवं तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट (म.प्र.) मैग्नीज ओर माइन, खसरा नं. 204/2, 206/1, रकबा 04.734 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर–200 टीपीए, ग्राम – सीतापटोर तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 204/2, 206/1, रकबा 4.734 हेक्टेयर, ग्राम सीतापटोर तहसील तिरोड़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वताया गया कि प्रकरण मुख्य अयस्क का है जिसका कुल रकबा 4.734 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज के अनुसार मैगनीज माइन में पेड दिखाई दे रहे है तथा पश्चिम दिशा में एक नहर 51 मीटर में स्थित है । डी. एफ.ओ द्वारा यह सूचित किया गया है कि आंवटित क्षेत्र वन क्षेत्र में अतः वन क्षेत्र में उत्खनन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है । पी.पी. द्वारा वताया गया कि किसी भी प्रकार की

भूमिगत खनन (Under Ground Mining) कार्य नही किया जावेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा है तथ उनके द्वारा स्टेज–1 फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त कर लिया गया है । अतएवं उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मानक टी.ओ.आर परिशिष्ठ ''डी'' में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊॅचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
2. लीज एरिया के पश्चिम दिशा में एक नहऱ 51 मीटर में स्थित है अतएव पी.पी. द्वारा इस नहऱ के संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
4. डी.एफ.ओ द्वारा यह सूचित किया गया है कि आंवटित क्षेत्र वन क्षेत्र में अतः वन क्षेत्र में उत्खनन हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है तथा यदि फॉरेस्ट क्लियरेंस स्टेज–1, क्लियरेंस प्राप्त किया है, विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. चूँकि प्रस्तावित क्षेत्र नहर के पास है, अतः ग्राउण्ड बाइब्रेशन स्टडी **कर रिपोर्ट** ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।

3. <u>प्रकरण क्रमांक 9030/2022 – मेसर्स मैग्नीज ओर (इंडिया) लि., गॉव एवं तहसील तिरोड़ी जिला बालाघाट (म.प्र.) मैग्नीज ओर माइन, खसरा नं. 157, रकबा 0.789 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता मैग्नीज ओर–500 टीपीए, ग्राम भरवेली, तहसील एवं जिला बालाघाट (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 157, रकबा 0.789 हेक्टेयर, ग्राम – भरवेली, तहसील एवं जिला बालाघाट (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वताया गया कि प्रकरण मुख्य अयस्क का है जिसका कुल रकबा 0.789 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज के अनुसार मैगनीज माइन रोड़ के ऊपर है तथा चारों ओर रहवासी क्षेत्र है । पी.पी. द्वारा वताया गया कि इस प्रकरण में भूमिगत खनन (Under Ground Mining) का कार्य किया जावेगा । अतएवं उपरोक्त

विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन मंत्रालय एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मानक टी.ओ.आर परिशिष्ठ ''डी'' में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊॅचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
2. चूॅकि प्रस्तावित क्षेत्र रहवासी क्षेत्र के ऊपर है, अतः ग्राउण्ड बाइब्रेशन स्टडी एवं सब्सीडेंस स्टडी कर रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
4. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
5. चूॅकि प्रकरण भूमिगत खदान है, जो रहवासी क्षेत्र खदान के ऊपर है, उसकी सुरक्षा हेतु एक अध्ययन किसी शासकीय संस्था से करबाकर, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. <u>प्रकरण कमांक 9021/2022 – श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. 1016, 1017/1–2पी, 1026पी, 1027पी, 1028पी, 1030 रकबा 08.094 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन– 3,00,000 टीपीए, ग्राम बठिया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1016, 1017/1–2पी, 1026पी, 1027पी, 1028पी, 1030 रकबा 8.094 हेक्टेयर, ग्राम बठिया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि खदान का कुल रकबा 8.094 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, पश्चिम दिशा में खदान से लगे हुए एवं खदान के अंदर कुछ मकान दिख रहे है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस लीज में पूर्व में 1999 तक खनन् कार्य किया गया है, उसके बाद से बंद है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने

हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊॅचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
2. खदान की पश्चिम दिशा में खदान से लगे हुए एवं खदान के अंदर कुछ मकान दिख रहे है, वृक्षारोपण जिनका विस्तृत विवरण, आर. एण्ड आर. के साथ ई.आई.ए. में प्रस्तुत किया जाये।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

5. <u>प्रकरण क्रमांक 9022/2022 – श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. 832पी, 835पी, 841पी, 1196, 1197, 1198, 1199 रकबा 08.094 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन – 3,00,000 टीपीए, ग्राम लटागांव, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 832पी, 835पी, 841पी, 1196, 1197, 1198, 1199 रकबा 8.094 हेक्टेयर, ग्राम लटागांव, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि खदान का कुल रकबा 8.094 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण भाग में एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा पूर्वी क्षेत्र में 66 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस लीज में पूर्व में 1992 तक खनन् कार्य किया गया है, तथा 1995 से खदान बंद है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान के दक्षिण भाग में एक कच्चा रोड़ निकल रहा है तथा पूर्वी क्षेत्र में 66 मीटर पर पक्का रोड़ स्थित है, इनकी संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
4. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊँचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।

6. <u>प्रकरण कमांक 9023/2022 – श्रीमती मंजू सिंह, पुष्पराज कॉलोनी, आंध्रा बैक के सामने, गली न. 1, पोस्ट एवं जिला सतना (म.प्र.) लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माईन, खसरा नं. पी303, पी309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, 399, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 448, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 06.794 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन–3,00,000 टीपीए, ग्राम बरहीया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. पी303, पी309,310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 44/8, 451, 452, 457, 458 एवं 459 रकबा 6.794 हेक्टेयर, ग्राम बरहीया, तहसील मैहर जिला सतना (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि खदान का कुल रकबा 8.094 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में उत्तर–पूर्वी दिशा में एक कच्चा रोड़ लीज क्षेत्र से निकल रहा है तथा दक्षिण दिशा में 40 मीटर पर नेशनल हाईवे, पश्चिम क्षेत्र में 40 मीटर पर तालाब तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 175 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस लीज में पूर्व में 1996–97 तक खनन् कार्य किया गया है, उसके बाद से बंद है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर,

एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में उत्तर–पूर्वी दिशा में एक कच्चा रोड़ लीज क्षेत्र से निकल रहा है तथा दक्षिण दिशा में 40 मीटर पर नेशनल हाईवे तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 175 मीटर पर आबादी है, अतः इनके संरक्षण की योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
4. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊँचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।
5. चूँकि प्रस्तावित क्षेत्र में पश्चिम क्षेत्र में 40 मीटर पर तालाब स्थित है, अतः उसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. चूँकि प्रस्तावित क्षेत्र आबादी के पास है, अतः ग्राउण्ड बाइब्रेशन स्टडी कर रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।

7. <u>प्रकरण क्रमांक 9025/2022 – श्रीमती सुमित्रा ग्रोवर, सिविल लाईन, रेस्ट हाउस के पास, नं.–1, पोस्ट एवं जिला कटनी (म.प्र.) क्षमता विस्तार लाईम स्टोन एवं डोलोमाईट माईन, खसरा नं. 240, 243पार्ट, 239, 242, 182, 246 रकबा 10.01 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता विस्तार लाईम स्टोन एवं डोलोमाइट – 1,00,000 से 3,50,000 टीपीए, ग्राम अमेहटा, तहसील विजयराघौगढ़ जिला कटनी (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आनलाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईम स्टोन एवं डोलोमाईट उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. पी303, पी309,310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, पी317, पी319, पी320, 432, 433, 434, 435, 436 444, 445, 446, 447, 44/8, 451, 452, 457, 458, 459 रकबा 10.01 हेक्टेयर, ग्राम अमेहटा, तहसील विजयराघौगढ़ जिला कटनी (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वताया गया कि प्रकरण मुख्य अयस्क का है जिसका कुल रकबा 6.794 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, उत्तर–पश्चिम दिशा में 30 मीटर हाइवे तथा दक्षिण दिशा में 20 मीटर पक्का रोड़ है । इसी उत्त्र–पूर्वी दिशा में 40 मीटर पर आबादी है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. उत्तर–पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर हाइवे, दक्षिण दिशा में 20 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्त्र–पूर्वी दिशा में 40 मीटर पर आबादी है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
5. चूँकि प्रकरण क्षमता विस्तार है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित पर्यावरणीय स्वीकृति पालन प्रतिवेदन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
6. चूँकि प्रकरण क्षमता विस्तार का है, अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गए वृक्षारोपण का क्षेत्र (लेट–लॉग सहित), वृक्षारोपण की संख्या उनकी प्रजाति एवं ड्रोन द्वारा दिए गए फोटो/स्टिल फोटो एवं वर्तमान स्थिति की जानकारी, ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत करें ।
7. चूँकि प्रस्तावित क्षेत्र आबादी के पास है, अतः ग्राउण्ड बाइब्रेशन स्टडी कर रिपोर्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।

8. <u>प्रकरण क्रमांक 9024/2022 – मेसर्स सीताराम स्टोन पार्टनर श्री धर्मेंद्र दानत्री, बी–11, पुरुषोत्तम बिहार, गोला का मंदिर जिला ग्वालियर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130 रकबा 4.640 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 2,28,000 मी.^{3}, ग्राम धरमन, तहसील गोहद जिला भिंड (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129, 1130 रकबा 4.640 हेक्टेयर, ग्राम धरमन, तहसील गोहद जिला भिंड (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण

रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 5044 दिनांक 14/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 37.408 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर रोड़ है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर रोड़ है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
5. खदान में पेड़ है, अतः वृक्षों की सूची (ट्री इंवेंट्री) प्रजाति नाम, संख्या, गोलाई एवं ऊँचाई सहित वृक्षारोपण ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करे ।

9. <u>प्रकरण क्रमांक 9026/2022 – मेसर्स के.पी. अवस्थी, पार्टनर बिचपुरा मेटल क्वेरी, बिचपुरा बरही, जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1038/2, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1033/1 रकबा 2.63 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 60,209 मी.^{3}, ग्राम बिचपुरा बरही, तहसील बरही जिला कंटनी (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1038/2, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1033/1 रकबा 2.63 हेक्टेयर, ग्राम बिचपुरा बरही, तहसील बरही जिला कंटनी (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र

क्रमांक 296 दिनांक 27/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 11 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 23.84 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में दक्षिण–पूर्वी दिशा में 280 मीटर पर आबादी है तथा खनन् क्षेत्र में एक पुराना पिट है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. दक्षिण–पूर्वी दिशा में 280 मीटर पर आबादी है अतः इसकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

10. Case No 9027/2022 M/s RCCPL Pvt. Ltd, (A M.P.Birla Group), Village - Bharauli, Post - Itahara, Tehsil - Maihar, Dist. Satna, MP Prior Environment Clearance for proposed 2X27.5MW Captive Power Plant and 300KVa DG set at Khasara No. 48/2, 191/2, 191/1GA, 194/2, 194/1, 47, 215/2, 192, 193, 215/1kh, 215/3, 215/5, 214, 216/1, 213, 212/2, 212/1P, 216/1, 217, 212/1, Village- Bharauli and Itahara, Tehsil: Maihar Dist.: Satna, (M.P.)

This is case of Prior Environment Clearance for proposed 2X27.5MW Captive Power Plant and 300KVa DG set at Khasara No. 48/2, 191/2, 191/1GA, 194/2, 194/1, 47, 215/2, 192, 193, 215/1kh, 215/3, 215/5, 214, 216/1, 213, 212/2, 212/1P, 216/1, 217, 212/1, Village- Bharauli and Itahara, Tehsil: Maihar Dist.: Satna, (M.P.)

The case was presented by the PP and their consultant and during presentation following details were provided.

- M/s RCCPL Pvt. Ltd (MP Birla Group) has proposed to set up 2x 27.5 MW coal-based power plant at villages Bharoli, Tehsil- Maihar Dist of Satna in MP state. Proposed Captive power plant is to be installed in the premises of operating Cement Plant to meet current and additional power requirement for LINE I and Proposed LINE II. at RCCPL Pvt Ltd, Maihar, District Satna M.P.
- M/s RCCPL, Maihar unit is located in Satna district of MP. This unit is an integrated cement plant and have one line Clinkerisation (10000 TPD), with two cement grinding mills & packing plant. At the same location, RCCPL planned to install another line of Clinkerisation of similar capacity in future. To meet out

the most of the it's power requirements, RCCPL have planned to install a captive power plant.

- RCCPL Pvt Ltd is operating cement plant with production capacity of clinker of 3.6 MTPA and cement of 5.0 MTPA, located at Villages Bharauli and Itahara, Maihar-Tehsil, Satna District, Madhya Pradesh.

The committee after presentation committee decided to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for carrying out EIA study with following additional TOR's and as per Annexure D:-

1. Furnish details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
2. The mode of transportation of the coal shall be discussed in the EIA report.
3. Present status of fly-ash utilization (if any) and utilization of quantity of fly ash after installation of 2x 27.5 MW coal-based power plants shall be provided in the EIA report.
4. Plume dispersion modeling shall be carridout to predict air quality wrt nearby habitations.

11. <u>प्रकरण क्रमांक 9012/2022 – श्री मनु मल्होत्रा, वार्ड न. 1, बरही तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 209/2 रकबा 01.35 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–20,001 मी.^{3}, ग्राम करोदीकलां तहसील बरही जिला कटनी (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 209/2 रकबा 1.35 हेक्टेयर, ग्राम ग्राम करोदीकलां तहसील बरही जिला कटनी जिला कंटनी (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 5342 दिनांक 07/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 09.85 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
2. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

12. Case No 8913/2022 Smt. Bharti Yadav, Lessee, House No. 162, Village - Mangeli, Post - Nigri, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (Stone - 9718 Cum per annum, Murrum - 3523 Cum per annum) (Khasra No. 24/2 Part), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) Env. Consultant Ambiental Global Private Ltd., Ghaziabad (U.P.)

This is case of Stone & Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 24/2 Part), Village - Manegaon, Tehsil - Jabalpur, Dist. Jabalpur (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है । प्रकरण सेक की 546वीं बैठक दिनांक 08/2/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु नियत था जिसमें परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहे ।

प्रकरण आज दिनांक 556वी बैठक दिनांक 02/03/22 एवं 546वीं बैठक दिनांक 08/2/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियेाजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

13. प्रकरण क्रमांक 9036/2022 – श्री जीवन रघुवंशी, ओनर, ग्राम अकोलिया तहसील एवं जिला धार (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1022/1/जी/2पेकी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन–14,550 मी.^{3}, ग्राम खेड़ा तहसील एवं जिला धार (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1022/1/जी/2 पेकी, रकबा 1.0 हेक्टेयर, ग्राम खेड़ा तहसील एवं जिला धार (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 276 दिनांक 18/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 07.762 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. प्रस्तावित खदान के दक्षिण दिशा में 300 मीटर पर व्हीकल टेंसटिग फेसिलिटी है अतः उसके संरक्षण की योजना ईआइए के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

14. <u>प्रकरण क्रमांक 9038/2022 – मेसर्स केपीटल मिनरल्स एवं माईनिंग, निवास 36 नयागॉव सोसायटी, रामपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) आयरन ओर माईन, खसरा नं. 1547, रकबा 04.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता आयरन ओर– क्षमता विस्तार 32,040 टन/वर्ष से लेटराईट – 33567 टीपीए तथा आयरन ओर – 10312 टीपीए ग्राम गांधीग्राम तहसील सिहोर, जिला जबलपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण आयरन ओर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1547, रकबा 4.50 हेक्टेयर, ग्राम गांधीग्राम तहसील सिहोर, जिला जबलपुर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वताया गया कि प्रकरण मुख्य अयस्क का है जिसका कुल रकबा 4.50 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । परियोजना प्रस्तावक ने वताया कि प्रकरण उत्पादन क्षमता विस्तार आयरन ओर– 32,040 टन/वर्ष से लेटराईट – 33567 टीपीए तथा आयरन ओर – 10312 टीपीए का है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, उत्तर–पश्चिम दिशा में 30 मीटर हाइवे तथा दक्षिण दिशा में 20 मीटर पक्का रोड़ है । इसी उत्त्र–पूर्वी दिशा में 40 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ब्लास्टिंग नहीं है, रॉक ब्रेकर से उत्खनन् कार्य किया जावेगा । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई. आई. ए. रिर्पाट तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं

जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. उत्तर–पश्चिम दिशा में 30 मीटर पर हाइवे, दक्षिण दिशा में 20 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्त्र–पूर्वी दिशा में 40 मीटर पर आबादी है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
5. चूँकि प्रकरण क्षमता विस्तार है, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रमाणित पर्यावरणीय स्वीकृति पालन प्रतिवेदन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

15. Case No 9039/2022 M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, Shri Vaibhav Rai, Director, 37 - 38, Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, MP

This is case of Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, MP.

The case was presented by the PP and their consultant wherein PP submitted the salient features of the project:

- The project site is free from any vegetation as well as habitation. There is no change in land-use will be done. As the project is proposed to develop a commercial warehouse and the landuse of the project will be same as commercial.
- Approx – 55% work completed.
- Some old structures will be demolished. Debris of construction waste will be used for filling or will be dumped out with consultation of Municipal Corporation or admin department.

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation

plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Status report of constriction took place so far.
2. Furnish details of CO_2 emission & quantification from different sources as DG sets and their management plan w.r.t. carbon foot print.
3. Fire NOC to be taken from the concerned department and submitted with EIA.
4. Project description, its importance and the benefits.
5. Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.
6. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.
7. Land use as per the approved Master Plan of the area, permission/approvals required from the land owning agencies, Development Authorities, Local Body, Water Supply & Sewerage Board etc.
8. Land acquisition status, R & R details (if any).
9. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
10. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PN2.5, SO2, NOx & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 5 locations in the study area of 10 Km.
11. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
12. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.)

13. Sources of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
14. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area
15. Management of solid waste and the construction & demolition waste for the project vis-à-vis the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction & Demolition Rules, 2016.
16. Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.
17. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
18. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
19. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by the accredited consultant.
20. Comprehensive Plantation scheme shall be discussed in EIA report.

16. <u>प्रकरण कमांक 9042/2022 – श्री के.के. गौतम, लीज ओनर, पुरानी वस्ती जलपा देवी वार्ड, गौतम लेन, जिला कटनी (म.प्र.) लाईम स्टोन माईन, खसरा नं. 15/1 पार्ट, रकबा 06.104 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता लाईम स्टोन एवं वेस्ट – 1,97,440 टन/वर्ष ग्राम भतोरा तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा ऑन लाईन प्राप्त यह प्रकरण लाईन स्टोन उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 15/1 पार्ट, रकबा 6.104 हेक्टेयर, ग्राम भटूरा तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा वताया गया कि प्रकरण मुख्य अयस्क का है जिसका कुल रकबा 06.104 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है तथा 01 माइंड आउटपिट, जिसमें पानी भरा हुआ है,

स्थित है। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में कुछ पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. खदान में पानी भरा हुआ माइंड आउटपिट है, अतः पिट की स्थिति तथा पानी निकासी की व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया जाय।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
5. खदान के पूर्व क्षेत्र में 75 मीटर पर पक्का रोड़ है, उसकी संरक्षण योजना, ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।

17. <u>प्रकरण क्रमांक 9043/2022 – श्री संजय मित्तल, ओनर, 11–12 दून मार्केट, जबलपुर रोड़ वरगावाँ, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज माइन, खसरा नं. 135, 136, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज (Average) – 3,01,999.40 टीपीए, ग्राम वडागाँव, तहसील बडवरा जिला कटनी (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण डोलोमाइट एवं क्वार्ट्ज उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 135, 136, रकबा 04.00 हेक्टेयर, ग्राम वडागांव तहसील बडवरा जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 665 दिनांक 25/02/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 15.31 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में पेड़ लगे दिख रहे है तथा पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रकरण में मुख्य रूप से रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जावेगा तथा कभी–कभी ब्लॉस्टिंग की जावेगी । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण,

वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. पश्चिम दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
3. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
4. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

18. <u>प्रकरण क्रमांक 9047/2022 – मेसर्स श्री मां नर्मदा एग्रोटेक एवं इन्फ्रस्टाचर लि., यू.जी. 47, ट्रेड सेंटर कंचनबाग मेंन रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 1/1/1, 1/1/1/2, 1/1/1/3, 1/2/1, 1/2/2 रकबा 01.90 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन– 14,700 मी.^{3} ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1/1/1, 1/1/1/2, 1/1/1/3, 1/2/1, 1/2/2 रकबा 1.90 हेक्टेयर, ग्राम धुरेरी तहसील देपालपुर जिला इंदौर (म.प्र.) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 124 दिनांक 10/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 09 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 19.732 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान की उत्तर दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. उत्तर दिशा में 90 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
3. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

19. <u>प्रकरण क्रमांक 9048/2022 – श्री अंकित गुप्ता, लीज ओनर, निवास रामकृष्ण नगर, जिला झाबुआ (म.प्र.) स्टोन क्वेरी, खसरा नं. 83, 84/1, 103/1 रकबा 02.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता स्टोन – 7,980 मी.^{3} ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।</u>

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण पत्थर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 83, 84/1, 103/1 रकबा 2.0 हेक्टेयर, ग्राम पीपलदेहला तहसील एवं जिला झाबुआ (म.प्र) पर स्थित है।

आज दिनांक 02/03/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म–2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) पत्र क्रमांक 19 दिनांक 10/01/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 08.15 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, पूर्व दिशा में खदान के अंदर शेड, उत्तर दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़ व खदान क्षेत्र में एक माइंड आउटपिट है । उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर–डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :–

1. खदान में पेड़ लगे हुए दिख रहे है, अतः वृक्षों की गणना (ट्री इंवेंट्री) ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
2. उत्तर दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़ है, अतः इनके संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।

3. खदान के अंदर पूर्व दिशा में शेड दिखाई दे रहे है, अतः इनकी वास्तविक स्थिति व उपयोग, ई.आई.ए. में स्पष्ट किया जाये ।
4. खदान में पानी भरा हुआ माइंड आउटपिट है, अतः पिट की स्थिति तथा पानी निकासी की व्यवस्था का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट में किया जाय।
5. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये ।
6. यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

DISCUSSION BASED ON QUERY REPLY SUBMITTED BY PP

20. Case No 6808/2020 Shri Karan Singh Chouhan, R/o Dubey Colony, Dist. Katni, MP – 483501 Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 2.19 ha. (Limestone – 25,804 tonne per annum, Dolomite – 5,430 tonne per annum) (Khasra No. 212, 508, 509), Village - Nanhwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP). Env. Consultant: CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad.

This is case of Limestone & Dolomite Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 212, 508, 509), Village - Nanhwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 2.19 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Tehsildar Office letter No. 384 dated: 22/11/2019 has reported that there are 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 4.29 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 426nd SEAC dated 27/02/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report forwarded through SEIAA on-line and the same was scheduled in the agenda.

In the 542nd SEAC meeting dated 21.01.2022 the EIA was presented by Env. Consultant Shri R.K. Choube from M/s. CSIR-Central Institute of Mining and Fuel Research, Dhanbad on behalf of PP , on behalf of PP . During presentation it was observed as per Google image based on coordinates provided by PP that lease is

excavated & pucca road is existed in the NW side at a distance of 318 m and 02-03 trees area existed within the lease area. Following salient features of the proposed project were submitted by PP:

- The excavation of Limestone will be done by using hand tools such as spades, hammer, crowbar, chisel etc. The loading of Limestone will be done with shovel-tipper combination and transportation will be done through hired trucks or tippers. Light drilling & blasting will be done. While planning the proposal for next financial year economic depth of the pit minimum degradation of land has been considered, in order to prevent haphazard excavation of pits and advancing towards N-S and E-W side covering existing pits.
- Mining will be carried out by developing systematic, regular and separate benches mineral to achieve desired production. During proposed to developed pit laterally towards all direction and depth also up to 385mrl.
- Haulage roads 5m wide will be laid at maximum 1: 16 gradient from surface (stack yard) to pit bottom at 385mrl within bye roads to faces of individual benches.
- Uniform 4 m high benches in manual mining will be developed (however sub benching will be done to facilitate jackhammer drilling if hard portion encountered during mining.

After presentation and deliberation, PP was asked to submit following information:

1. PP shall submit old production taken from the year 2003-2014 this was also TOR point.
2. PP shall proposed NE &SE area where root stocks are existing as non- mining area.
3. Soil profile in the lease periphery.
4. Revises plantation species (site specific, Barrier zone and on approach road) as suggested by the committee.
5. PP commitment that Plantation scheme will be completed within initial 01 year of the project and causality replacement shall be done from 02 years .
6. Revised CER incorporating physical and financial target with allocation of some budget for the wild life rescue centre in the Kanha National Park, Mandla with the consultation of Director Kanha NP, as suggested by committee during meeting.
7. In the EIA, reply to standard TOR S. no. 27, Fig. 2.2 is not legible; a legible copy of the figure may be sumitted.

PP vide their letter dated 22/02/2022 uploaded online query reply well as on "Parivesh Portal". which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EMP and other submissions made by the PP were found satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Limestone – 25,804 tonne per annum, Dolomite – 5,430 tonne per annum.
2. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.8.38 Lakh as capital and Rs. 02.58 Lakh/year.
3. As proposed, a minimum of 2500 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme.
4. Under CER following activities were submitted by PP:

S. No.	Activity	Cost
1.	Apart from regular health checkup for which Rs 50,000/- is kept in this head for mine laborers, physical and financial support will be given for the wild life rescue centre as mine owner is already involved in Bandhavgarh Buffer zone welfare activities (documents attached in support of claim).	Rs 50,000/-
	As advised lessee KARAN SINGH CHOUHAN has made communication with the Director of kanha national park for ways and means to support wild life rescue centre in kanha national park. (letter attached)	

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
	Lease periphery approach road, Haul road, reclaimed area, undisturbed area, buffer zones and government premises with consent.	Neem, Sheesham, Siris, Mahua, Bel, Aam, Impli and other native species suggested by Officials.	25000
		योग	2500

21. <u>Case No 8882/2021 Shri Himanshu Dubey S/o Shri Brijmohan Dubey, Ward No. 2, Balaji Nagar Tehsil Pachore District - Rajgarh, MP - 465683 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.880 ha. (5001 Cum per annum) (Khasra No. 54/2), Village - Nagar Pachore, Tehsil - Pachour, Dist. Rajgarh (MP) RQP Shri Ram Vishal Shukla</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 54/2), Village - Nagar Pachore, Tehsil - Pachour, Dist. Rajgarh (MP) 1.880 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

The case was presented by RQP Shri Ram Vishal Shukla on behalf of PP in the 541st SEAC meeting dated 20/01/2022. During presentation, PP showed various documents such as lease sanction order, Gram Sabha, DFO NOC, Tehsildar Certificate, MO Certificate, Approved Mine Plan, Khasra Panchshala, P-II, DSR, EMP & PFR for appraisal of project before the committee. It was observed by Committee that as per Collector Office (Ekal Praman-patra) letter No. 1475 dated 30/11/21 has reported that there are 01 more mine is sanctioned for renewal which is at present not operating and lease validity have been expired of 02 other mines existed within 500 meters around the said mine hence total area of shall be 2.880 ha., including this mine. As per Google image based on online KML file uploaded by PP, it was observed that lease is already excavated PP submitted that lease area is already excavated. PP submitted that it is very old pit earlier this lease was sanctioned to other PP and they have got the lease in such condition and the pit has shown on surface map of approved Mining plan. Also PP has submitted isolated houses located in the SE corner of the lease are belonging to the mine owner. PP also submitted that no blasting shall be carried out during proposed for mining operation. Around 500 meters following sensitive features were observed of the lease area:

Sensitive Features	**Approximate aerial distance from the lease area in meters**	**Direction**	**Remarks**
Water impound structure	265	NE	Provision of Garland drain & settling tanks.
Natural drain	247	North	Provision of Garland drain & settling tanks.
Industrial shed	>400	SE	PP submitted that this is a soya plant. Blasting is not proposed.
Houses/structures	Within lease /Adjacent	SW corner	PP submitted these houses belonging to PP.
Some Trees	Within lease	-	Tree management plan

After presentation the committee asked to submit following details:

- PP's commitment that no blasting is proposed for mining operation.
- Soil profile study of barrier zone particularly in the East-West side of the lease.

PP vide their letter dated 10/02/2022 uploaded online query reply well as on "Parivesh Portal". which was placed before the committee and the same found satisfactory. The EMP and other submissions made by the PP were found satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC subject to the following special conditions in addition to the standard conditions at annexure 'A':

1. Production shall be as per mine plan with quantity not exceeding for Stone 5001 cum per annum.
2. No blasting shall be carried out for mining operation.
3. A budgetary provision for Environmental management Plan of Rs.12.10 Lakh as capital and Rs. 04.185 Lakh/year.
4. As proposed, a minimum of 2400 trees shall be planted as per the submitted plantation scheme.
5. Under CER following activities were submitted by PP:

	FOR SOCIAL WELFARE (Please provide physical targets only)	
S. No.	**Activity**	**Cost**
1.	01 computer with printer and Computer table and 10 plastics chairs office table in Govt. Higher Secondary School of Nagar Pachore village.	60,000.00
2.	20 shady trees (Kadamb, Kachnar, Karanj, Arjun, Bahunia etc.) will be planted along the boundary wall of Govt. Higher Secondary School of Nagar Pachore village.	5,000.00
	Total	65,000.00

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षो का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	Apporach road	Neem, Peepal, Karanj, Khamer, Kachnar, Putranjeeva, Pakad, Arjun etc.	1000
2	Gram Panchyat	Neem, Peepal, Karanj, Khamer, Kachnar, Putranjeeva, Pakad, Arjun etc.	1400
		योग	2400

22. Cases where PP has not submitted the desired information/pending since long/ remains absent from the SEAC meeting:

Following cases were appraised in various SEAC meetings wherein online query/clarification was sought from PP but even after 30 days reply/response from the PP is awaited:

SN	Case No. Activity	SEAC Meeting details in which query/clarification was sought from PP
1.	Case No 7365/2020 M/s Bamdev Global, Authorized Person, Shri Upendra Gupta, E-91, Shree Nath Vihar, Chilla Road, Dist. Banda, UP - 210001 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 7.0 ha. (35000 cum per annum) (Khasra No. 01) at Village- Nachankheda, Tehsil- Burhanpur, District- Burhanpur (MP) (EIA)	Q 537 dated 24/12/21 A- 544th meeting 28/01/22
2.	Case No 7364/2020 M/s Bamdev Global, Authorized Person, Shri Upendra Gupta, E-91, Shree Nath Vihar, Chilla Road, Dist. Banda, UP - 210001, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (30000 cum per annum) (Khasra No. 122, 318, 01, 52 Parts) at Village- Gavhana, Tehsil- Burhanpur, District- Burhanpur (MP) (EIA)	Q 537 dated 24/12/21 A-544th meeting 28/01/22
3.	Case No 8888/2021 Shri Surendra Mohan Agrawal S/o Omprakash Agrawal, Civil Lines, Dist. Jhansi, UP - 472446, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.113 ha. (20628 Cum per annum) (Khasra No. 159), Village - Basoba, Tehsil - Orchha, Dist. Niwari (MP)	Query – 544th dated 28/1/2022
4.	Case No 8884/2021 Shri Pankaj Nagar S/o Shri Bhagirath Nagar, Nivasi-Bordikalan, Teh- Ichhawar, Dist- Sehore, MP - 466115, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5001 Cum per annum) (Khasra No. 356/3/1), Village - Bordikalan, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP)	Query – 544th dated 28/1/2022

5.	Case No 8897/2021 Shri Arun Tyagi S/o Babban Tyagi, House no. -213, EWS, North T.T. Nagar, Dist. Bhopal, MP - 462003, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (9060 Cum per annum) (Khasra No. 588/1/1k), Village - Khauri, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal (MP)	Query – 544th dated 28/1/2022
6.	Case No 7229/2020 Shri Sunny Goyal S/o Shri Motilal Goyal, R/o Hariyana Bhawan, Panna Naka, Dist. Satna, MP - 485446, Email - , Mobile – 9026123876 Prior Environment Clearance for approval of Stone Mining in an area of 2.283 ha. (15000 cum/year) (Khasra No. 1032/2, 1035/3, 3/1/KA, 3/1/Kha/3/1/GA, 3/1/GHA, 3/2, 3/3) at Village- Gangwariya & Sukulgawan, Tehsil- Nagod, District- Satna (MP) (EIA)	Query – 545th dated 29/1/2022
7.	Case No 7231/2020 Shri Sunny Goyal S/o Shri Motilal Goyal, R/o Hariyana Bhawan, Panna Naka, Dist. Satna, MP - 485446, Prior Environment Clearance for approval of Stone Mining in an area of 2.974 ha. (20000 cum/year) (Khasra No. 10/1, 10/2, 12/1, 12/2/1, 12/3, 12/4) at Village- Baraj, Tehsil- Nagod, District- Satna (MP) (EIA)	Query – 545th dated 29/1/2022
8.	Case No 8491/2021 Shri Shubham Goyal, Hariyana Bhawan, Panna Naka, Dist. Satna, MP - 485446, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.70 ha. (5000 cum per annum) (Khasra No. 267/2, 268/1Kha, 268/2, 271//Gya/1, 271/1/Gya/2), Village - Badhaw Ubari, Tehsil - Nagod, Dist. Satna (MP) (EIA)	Query – 545th dated 29/1/2022
9.	Case No 7230/2020 Shri Shubham Goyal , R/o Hariyana Bhawan, Panna Naka, Dist. Satna, MP - 485446, Prior Environment Clearance for approval of Stone Mining in an area of 1.578 ha. (5000 cum/year) (Khasra No. 158/1KA) at Village- Bara Pathar, Tehsil- Nagod, District- Satna (MP) (EIA)	Query – 545th dated 29/1/2022
10.	Case No 8818/2021 Shri Jakiuddin Kaji, Juna Bazar, Alot, Dist. Ratlam, MP - 457118, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (Stone - 10453 Cum per annum, Murrum - 4547 Cum per annum) (Khasra No. 172), Village - Malya, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam (MP)	Query – 545th dated 29/1/2022

Committee observed that PP of above cases have not submitted the desired information and cases are pending since long. In the entire above cases online query was raised through EDS. As per MoEF&CC OM dated 15/03/21 if:

"the reply to EDS is not received on PARIVESH within 30 days, the proposal will be excluded from the pendency list shown on PARIVESH. However, the PP can relist the proposal through their respective login provisions, as and when they want to submit the EDS reply".

Recently, SEIAA vide letter no. 2590 dated 15/12/21 has communicated policy decision taken in their 694th meeting dated 26/11/2. According to the policy decision taken by SEIAA at point no.08 *(SEAC should make final recommendations within 30 days for EC/ TOR)*.

The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊँचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.

b. Mining Lease area of the project (in ha.)
c. Production capacity of the project.

30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
    vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
    नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
    नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'
Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.)
    c. Production capacity of the project.

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'
General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

    - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
    - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
    - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
    - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
    - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
    - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
    - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
    - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
    - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
    - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।

नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– पौधों की ऊॅचाई/गोलाई –

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊॅचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.